गुजरात राज्य

बनाम

गिरिश राधाकृष्णन वर्दे

(आपराधिक अपील सं. 1996/2013)

25 नवंबर, 2013

(न्यायमुर्ति जी. एस. सिंघवी और ज्ञान सुधा मिश्रा)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-अध्याय XII, XIV और XV धारा 154 और 190- मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद के माध्यम से दर्ज मामला [धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद पर संस्थित मामला] और पुलिस के समक्ष धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एफ. आई. आर. के आधार पर दर्ज मामला। दोनों के बीच अन्तर-उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिन्होंने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को धारा 154 द.प्र.सं. के तहत दर्ज एफ.आई.आर. पर पुलिस जांच के बाद प्रस्तुत आरोप पत्र में भारतीय दण्ड संहिता की अतिरिक्त धाराएं जोडने की अनुमति दी थी। दण्ड प्रक्रिया संहिता-औचित्य-प्रतिपादित: मजिस्ट्रेट ने आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के बाद धाराओं को जोड़ने की अनुमति दी, यह ध्यान में रखते हुए कि तत्काल मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष 190 सीआरपीसी दर्ज शिकायत मामले से

उत्पन्न नहीं हुआ था लेकिन एक पुलिस रिपोर्ट/ एफ.आई.आर से उत्पन्न हुई एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर 154 सीआरपीसी के आधार पर दर्ज किया गया हालाँकि, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय को मजिस्ट्रेट और शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाई जाने वाली कार्रवाई का सही तरीका निर्दिष्ट करना चाहिए था, जिसमें विफलता के कारण मामला इस मुकदमे में उलझ गया जिससे मुकदमे की सुनवाई में बाधा उत्पन्न हुई। -उच्च न्यायालय के आदेश का नतीजा यह है कि- अपीलार्थी गुजरात राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष को कम उपचार प्रदान किया जा सकता है- हालांकि, उच्च न्यायालय यह देखने में सही हो सकता है कि विचारण न्यायालय को आरोपों को संशोधित करने से नहीं रोका गया था । मुकदमे के दौरान उचित चरण में धाराओं को शामिल या बाहर करके, न्याय और निष्पक्षता के हित में यह स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट करने के लिए कर्तव्य था कि विचारण न्यायालय धारा 211 सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने के चरण में धाराएं जोड़ने की याचिका की अनुमति देगा और उस पर विचार करेगा, क्योंकि मामला एक पुलिस मामले से उभरा है, न कि मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत मामले से, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अधिक न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है-सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता अपीलकर्ता-राज्य, विचारण न्यायालय द्वारा आरोप तय करने के समय एफआईआर और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर धाराएं जोड़ने से संबंधित सभी प्रश्न

उठाएगा। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया था जिसके द्वारा उन्होंने शिकायतकर्ता को पुलिस जांच के बाद प्रस्तुत आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 364, 394 और 398 जोड़ने की अनुमति दी थी।

उपरोक्त अपील में निर्धारण के लिए मुख्य प्रश्न यह था कि क्या मजिट्रेट सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस मामले की जांच पूरी होने पर पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले को आईपीसी की अतिरिक्त धाराएं जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

अपील का निपटारा करते हुए, अदालत ने अभिनिर्धारित किया:

1- मौजूदा मामले में, पूरा विवाद प्रक्रियात्मक उलझन और संज्ञान लेते समय विचारण न्यायालय द्वारा अपनाये जाने वाले सही कदम के इर्द-गिर्द घूमता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत के माध्यम से दर्ज किए गए मामले के बीच के अंतर को आमतौर पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत शिकायत मामले के रूप में जाना जात है और पुलिस के समक्ष सीआरपीसी की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज मामला, छूट गया प्रतीत होता है, जिसका अर्थ है कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी मामले में

अपनाई जाने वाली दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 के तहत निर्धारित प्रक्रिया और मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज शिकायत के आधार पर मामलों के लिए अध्याय XIV और अध्याय XV के तहत निर्धारित प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है। (पैरा 11] [940-बी-ई]

2- दण्ड प्रक्रिया संहिता में अंतर्निहित प्रावधान के तहत यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो कोई भी किसी अपराध की जानकारी देना चाहता है तो वह या तो मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष पेश हो सकता है। यदि शिकायत किया गया अपराध गैर-संज्ञेय है, तो पुलिस अधिकारी या तो शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का निर्देश दे सकता है या वह अनुमति प्राप्त कर अपराध का अनुसंधान कर सकता है इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और भले ही खुलासा किया गया अपराध गंभीर हो, मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने और कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम है, यह मजिस्ट्रेट के लिए खुला है लेकिन जांच का निर्देश पुलिस को देना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार अपराधों को अदालत में ले जाने के लिए दो एजेंसियों की स्थापना की गई है।[पैरा 11] [941-सी-ई]

3- सीआरपीसी ने स्पष्ट रूप से एक शिकायत मामले में जांच करने और पुलिस जांच के आधार पर मजिस्ट्रेट की शक्तियों को वर्णित करने वाले दो तरीकों को शामिल किया है। एक पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के

आधार पर जहां पुलिस के जांच अधिकारी अध्याय XII के तहत जांच करते हैं और इन प्रक्रियाओं के संबंध में बिल्कुल कोई अस्पष्टता नहीं है (पैरा 15] [943-जी-एच]

4- इस स्पष्ट प्रावधान के तहत पुलिस रिपोर्ट पर आधारित एक मामला और अध्याय XIV और XV के तहत एक मजिस्ट्रियल शिकायत, जब किसी दिए गए मामले में सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करने की बात आती है, तो प्रभावित पक्ष अक्सर असमंजस की स्थिति में फंस जाते हैं। जैसा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत के आधार पर मामले से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति के बाद से तत्काल मामले में हुआ है और पुलिस रिपोर्ट/एफआईआर पर आधारित पुलिस शक्तियों को ओवरलैप करने की अनुमति दी गई है और दो अलग-अलग कार्रवाई को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है जो कि सही प्रक्रिया नहीं है क्योंकि यह सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यदि पुलिस द्वारा एफआईआर के आधार पर धारा 154 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है और जांच के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो एफआईआर के आधार पर कौन सी धाराएं लागू होंगी और जांच के दौरान आरोप पत्र में एकत्रित सामग्री के आधार पर कौन सी धाराएं लागू होंगी, इसका सही चरण तभी निर्धारित किया जाएगा। उपयुक्त ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप तय करने का समय वैकल्पिक रूप से, यदि मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज शिकायत से उत्पन्न होता है, तो सीआरपीसी की धारा 190 और 200

के तहत निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से पालन करना होगा (पैरा 16] [944-ए-ई]

5- चूंकि मौजूदा मामला पुलिस के समक्ष दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, इसलिए धाराएं जोड़ने या घटाने का सही चरण आरोप तय करते समय निर्धारित करना होगा, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने फैसले और आदेश में कारण नहीं बताए हैं। ऐसा करने के लिए सटीकता और स्पष्टता और यह रिकॉर्ड करके आकस्मिक अवलोकन किया गया है कि उचित चरण में विचारण न्यायालय के पास यह निर्धारित करने की शक्ति होगी कि मामले को अंतिम रूप से परीक्षण के लिए भेजे जाने से पहले कौन सा प्रावधान लागू किया जाना है। उच्च न्यायालय के आदेश का नतीजा अपीलकर्ता-गुजरात राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष को कम राहत प्रदान की जा सकती है क्योंकि मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है जहां अभियोजन पक्ष के पास याचिका में सुधार या सराहना के लिए कोई उपाय नहीं बचेगा कि क्या इसमें शामिल किया जाना है या नहीं। अतिरिक्त आरोपों के बहिष्कार की अनुमति दी जा सकती है वास्तव में, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनके समक्ष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण दायर की गई थी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार के गलत

प्रयोग के आधार पर पुनरीक्षण की अनुमति दे सकते थे, जिन्होंने भी आरोप पत्र में तीन और धाराएं जोड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बजाय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ऐसा करने से सीधे तौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है, न कि खुद को क्षेत्राधिकार की त्रुटि के संबंध में प्रश्न पर विचार करने और मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाए जाने वाले सही तरीके को निर्धारित करने तक सीमित रखने के बजाय, वास्तव में, कार्रवाई का सही तरीका उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए था। साथ ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-गुजरात राज्य को सीआरपीसी की धारा 228 के तहत आरोप तय करते समय आरोप जोड़ने का सवाल उठाने की अनुमति दे दी और बिना निर्धारित किए मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिए एक व्यापक आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। प्रभावित पक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्रवाई का सही तरीका जिसके परिणामस्वरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा तीन आदेश पारित किए गए, फिर भी यह कार्रवाई के उचित तरीके पर प्रकाश डालकर विवाद का समाधान नहीं कर सका। अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाया जाना - गुजरात राज्य के साथ-साथ मजिस्ट्रेट ने भी आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद धाराएं जोड़ने की अनुमति दी, जिसमें यह गायब था कि मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज शिकायत मामले से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि एक पुलिस रिपोर्ट से

उत्पन्न मामला था, जो एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर थी। (पैरा 17] [944-एफ-एच; 945-ए-जी]

6- हालांकि यह न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को मंजूरी नहीं देता है, जिन्होंने आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद आरोप पत्र में तीन धाराएं जोड़ने की अनुमति दी थी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय को मजिस्ट्रेट और शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाई जाने वाली कार्रवाई का सही तरीका निर्दिष्ट करना चाहिए था, जिनकी विफलता के कारण मामला उलझ गया जिससे मुकदमे की सुनवाई में बाधा उत्पन्न हुई। [पैरा 18] [945-जी-एच(946-ए-बी]

7- उच्च करन्यायालय के आदेश को इस हद तक स्पष्ट किया गया है कि अपीलकर्ता गुजरात राज्य एफआईआर के आधार पर धाराएं जोड़ने और आरोप तय करने के समय जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से संबंधित सभी प्रश्न उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। ट्रायल कोर्ट द्वारा चूंकि मामला सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर एक पुलिस मामले से उत्पन्न हुआ है, न कि सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज शिकायत मामले से, इस प्रकार उच्च न्यायालय हालांकि आक्षेपित आदेश में सही हो सकता है। ट्रायल कोर्ट को ट्रायल के दौरान उचित चरण में धाराओं को शामिल या बाहर करके आरोपों

को संशोधित करने से नहीं रोका गया था, यह स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट करने के लिए न्याय और निष्पक्षता के हित में बाध्य था कि ट्रायल कोर्ट धाराएं जोड़ने की याचिका की अनुमति देगा और उस पर विचार करेगा। सीआरपीसी की धारा 211 के तहत आरोप तय करने का चरण, क्योंकि मामला एक पुलिस मामले से उभरा है, न कि मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत का मामला है ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अधिक न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है। [पैरा 19] [946-बी-ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1996/2013

गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद के विशेष आपराधिक अपील संख्या 2477/2010 में निर्णय और आदेश दिनांक 08.04.2011 से।

अपीलकर्ता के लिए शमिक संजनवाला, हेमंतिका वाही।

प्रतिवादी के लिए डूंगर सिंह, ऋषभ संचेती टी महिपाल।

न्यायमुर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, द्वारा दिया गया निर्णय -अनुमति प्रदान की गई।

2- विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, जिसकी सुनवाई एडमिशन स्तर पर ही की गई थी, विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 2477/2010 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 8.04.2011 के विरूद्ध निर्देशित है। जिसके तहत विद्वान एकल

न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-गुजरात राज्य द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिसा द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा। जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया था जिसके द्वारा उन्होंने शिकायतकर्ता को पुलिस जांच के बाद प्रस्तुत आरोप पत्र में भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 364, 394 और 398 जोड़ने की अनुमति दी थी।

3- उक्त अपील में निर्धारण के लिए यह मुख्य प्रश्न है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी) के अध्याय XV के तहत "मजिस्ट्रेट को शिकायत" शीर्षक के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को धारा 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच पूरी होने पर पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद आईपीसी की अतिरिक्त धाराओं को आरोप पत्र में जोड़ने के लिए देने की अनुमति दी जा सकती है।

4- मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से पता चलता है कि 27-03-2009 को धारा 365, 387,511, 386, 34, 120-बी और 506(2) आईपीसी और आयुद्ध अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1) (ए) के तहत एफआईआर से पता चला कि सूचनाकर्ता/शिकायतकर्ता-दीपककुमार धीरजलाल ठक्कर निवासी डीसा तालुका साईं बाबा के मंदिर में बैठे थे,

जिनके खिलाफ आरोपियों ने अभियुक्त संख्या एक के साथ मिलकर अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश रची, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी आरोपी व्यक्तियों के साथ पंजीकरण संख्या जीजे-1 -एचपी-1 वाली एक ऑल्टो कार में शिकायतकर्ता की ओर आया और मंच से ही देशी पिस्तौल/रिवाल्वर लेकर शिकायतकर्ता की और दौडा। वहां पहुंचने पर, प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता की ओर पिस्तौल तान दी और उससे पैसे की मांग की इससे पहले कि पीड़ित-शिकायतकर्ता से की गई मांग के संबंध में कुछ समझ पाता या स्थिति की प्रकृति को समझ पाता, प्रतिवादी-आरोपी के साथ-साथ अन्य आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को पकड़ लिया और उसका अपहरण करने की कोशिश की, शिकायतकर्ता को लूटने और अपहरण करने के लिए प्रतिवादी द्वारा रची गई इस सुनियोजित और जानबूझकर साजिश की त्वरित प्रतिक्रिया में, शिकायतकर्ता ने शोर मचाया जिसके परिणामस्वरूप आस-पास खड़े लोग तुरंत भाग गए। अपराध स्थल पर लोगों की भीड़ को देखते हुए, आरोपी व्यक्ति तुरंत कार में बैठ गया और घटनास्थल से भाग गया। यह पहली बार नहीं था जब प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ ऐसा अपराध किया गया था बल्कि एक पूर्व अवसर पर भी प्रतिवादी ने 50,000 रुपये की जबरन वसूली की थी, शिकायतकर्ता को मृत्यु का भय दिखाकर हालांकि, जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें यहां पहले उल्लिखित धाराएं शामिल थीं, लेकिन आईपीसी

की धारा 364, 394 और 398 शामिल नहीं थीं, जिन्हें अभियोजन के अनुसार शामिल करवाना चाहता है।

5- पुलिस अनुसंधान पूरा होने के बाद दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में और विद्वान मजिस्ट्रेट डीसा के समक्ष पुलिस द्वारा एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें धारा 365, 511, 387, 386, 34, 120-बी और 506(2½ के साथ-साथ धारा 25 (1½(ए ½ आयुध अधिनियम भी शामिल थी। शिकायतकर्ता ने देखा कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी-अभियुक्त ने पिछले अवसर पर शिकायतकर्ता से 50,000/ रुपये लूट लिए थे और इस बार फिर से शिकायतकर्ता को लूटने और अपहरण करने का प्रयास किया लेकिन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 364, 394 और 398 के तहत दंडनीय अपराध शामिल नहीं थे। आरोप पत्र जो प्रतिवादी और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया था, उक्त त्रुटि को सुधारने के लिए शिकायतकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की अन्य धाराएं 364, 394 और 398 जोड़ने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट डीसा के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिन्होंने पक्षों को सुनने के बाद आवेदन संख्या 1754/2009 को स्वीकार करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 364, 394 और 398 को आरोप-पत्र में जोड़ने की अनुमति दी गई।

6- प्रतिवादी-अभियुक्त ने आरोप-पत्र में धाराएं शामिल करने और जोड़ने की अनुमति देने वाले उपरोक्त आदेश से व्यथित और असंतुष्ट

होकर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डिसा के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण को पेश की जिस पर विद्वान तृतीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2010 को रद्द कर दिया और दिनांक 23.09.2010 के आदेश द्वारा सिविल पुनरीक्षण की अनुमति दी।

7- अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, जिन्होंने आरोप पत्र में धाराएं जोड़ने की अनुमति देने वाले सीजेएम के आदेश को रद्द कर दिया और इसलिए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 2477/2010 दायर की गई।

8- गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2010 के आदेश को बरकरार रखा, जो अपीलकर्ता के अनुसार अवैध और अनुचित है क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश, जिन्होंने मामले को सुनवाई के लिए सौंपने से पहले आरोप पत्र में आईपीसी की तीन धाराओं को जोड़ने की अनुमति दी थी को विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इसे रद्द करते समय कोई ठोस कारण नहीं बताया।

9- अपीलकर्ता-गुजरात राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश की आलोचना करते हुए कहा था कि मजिस्ट्रेटों को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए न केवल तब जब उसे किसी तीसरे व्यक्ति से अपराध किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि वहां भी जहां उसे जानकारी हो या यहां तक कि संदेह हो कि अपराध किया गया है। इस तर्क को विस्तार से बताते हुए, यह आगे तर्क किया गया कि मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सीआरपीसी के अध्याय 15 में परिकल्पित शिकायत पर विचार करने के लिए और जब शिकायत प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट धारा 200 और सीआरपीसी के अध्याय 15 में आने वाली धाराओं के तहत आगे बढ़ने के उद्देश्य से अपना दिमाग लगाता है, तो कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट ने धारा 190 के अर्थ के भीतर अपराध का संज्ञान ले लिया है। सीआरपीसी में यह भी प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी पर भी संज्ञान ले सकता है और इस प्रकार मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर कोई बाधा या प्रतिबंध नहीं है, जब वह कार्यवाही के संचालन के लिए दर्ज की गई शिकायत के आधार पर अधिक धाराएं शामिल करना उचित समझता है। अभियुक्त का मुकदमा और मजिस्ट्रेट धारा 190 (1) (सी) के तहत अपराध का संज्ञान इस आधार पर लेने के लिए स्वतंत्र है कि अंतिम रिपोर्ट और उसके सामने रखे हुए पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए यदि उसके पास अपराध पर संदेह करने का कारण है कि अपराध किया गया है,

धारा 190 (1) (सी) के तहत अपराध का संज्ञान लेना मजिट्रेट के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इसलिए यदि मजिस्टेट ने पाया कि धारा 364, 394 और 398 के तहत अन्य अपराधों के लिए भी प्रतिवादी/अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री थी। आईपीसी में उन धाराओं को आरोप पत्र में जोड़ने की अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध समुचित सामग्रियों के आधार विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा इन्हें सही तरीके से जोड़ा गया था।

10- प्रतिवादी के अधिवक्ता ने हालांकि उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आधार पर भरोसा किया, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अतिरक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखने के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीसा के आदेश को रद्द करते हुए उन तीन धाराओं को शामिल करने की अनुमति दी थी जो आरोप पत्र दाखिल करने के समय शामिल नहीं थीं। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने हालांकि आरोप पत्र में अतिरिक्त धाराएं जोड़ने की अनुमति देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मंजूरी दे दी। यह विचार किया गया कि यदि ट्रायल जज ने देखा कि आईपीसी की कुछ धाराओं का आरोप पत्र में उल्लेख नहीं किया गया था और ट्रायल के दौरान, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आईपीसी के प्रावधानों के तहत कोई अन्य अपराध बनता है, तो विचारण न्यायालय को रोका नहीं गया है और उसके पास धाराएं जोड़ने के लिए उचित आदेश पारित करने की सभी शक्तियां प्राप्त हैं और इसलिए,

विचारण न्यायालय ने आईपीसी की तीन धाराओं को आरोपपत्र में जोड़ने की अनुमति देकर, प्रस्तुत किए जाने के बाद शिकायतकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है।

11- इस अपील में उठाए गए विवाद से यह स्पष्ट है कि पूरा विवाद प्रक्रियात्मक खींचतान और संज्ञान लेते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए जाने वाले सही रास्ते के इर्द-गिर्द घूमता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में ऐसा प्रतीत होता है कि पहले शिकायत के माध्यम से दर्ज किए गए मामले के एवं एफ.आई.आर. के आधार पर दर्ज किये गये मामले बीच में अंतर है। मजिस्ट्रेट को आम तौर पर सीआरपीसी की धारा 190 के तहत शिकायत मामले के रूप में जाना जाता है और पुलिस के समक्ष सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज मामले को नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया के बीच अंतर सीआरपीसी के अध्याय XII को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एक मामले में अपनाया जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज शिकायत के आधार पर मामलों के लिए अध्याय XIV और अध्याय XV के तहत निर्धारित प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया या नजरअंदाज कर दिया गया है। यह इस स्तर पर रिकॉर्ड करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है। 'शिकायत' शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से लगाए गए आरोप, इस तथ्य के कारण संहिता के तहत कार्रवाई

करने के लिए कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है लेकिन इसमें सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज की गई पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। सीआरपीसी की धारा 190(1) में मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों के संज्ञान का प्रावधान है और यह तीन तरीके प्रदान करता है जिसके द्वारा इस तरह का संज्ञान लिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:-

(ए) ऐसे तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं;

(बी) ऐसे तथ्यों की लिखित रूप में एक पुलिस रिपोर्ट पर-यानी, किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का गठन करने वाले तथ्य;

(सी) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर या मजिस्ट्रेट के स्वयं के ज्ञान या संदेह पर कि ऐसा अपराध किया गया है।

इन प्रावधानों की जांच से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब एक मजिस्ट्रेट उन तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर अपराध का संज्ञान लेता है जो इस तरह के अपराध का गठन करते हैं, एक मामला मजिस्ट्रेट की अदालत में शुरू किया गया है और ऐसा मामला एक शिकायत पर शुरू किया गया है। फिर, जब एक मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी द्वारा

लिखित ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो यह एक पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट की अदालत में शुरू किया गया मामला है। सीआरपीसी में अंतर्निहित योजना स्पष्ट रूप से बताती है कि जो कोई भी अपराध की जानकारी देना चाहता है वह या तो मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकता है। यदि अपराध गैर-संज्ञेय है, तो पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का निर्देश दे सकता है या वह मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त कर सकता है और अपराध की जांच कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और भले ही खुलासा किया गया अपराध गंभीर हो, मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने और कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम है। यह मजिस्ट्रेट के लिए खुला है लेकिन उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। पुलिस द्वारा जांच का निर्देश देने के लिए इस प्रकार अपराधों को अदालत में ले जाने के लिए दो एजेंसियों का गठन किया गया है।

12- लेकिन उक्त प्रकरण एक मामले से उत्पन्न होता है जो एक पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है क्योंकि धारा 154 सीआरपीसी के तहत डीसा पुलिस स्टेशन में पुलिस के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी इसलिए, सीआरपीसी के अध्याय XII के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई और उसके बाद आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। इस स्तर पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपपत्र प्रस्तुत

करने के बाद शिकायतकर्ता के एक आवेदन पर विचार किया एवं आरोप पत्र में तीन अन्य धाराएं जोड़ने के लिए, जो पूरी तरह से गायब है। यदि यह शिकायतार्ता द्वारा धारा 190ए सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया गया शिकायती मामला था, स्पष्ट रूप से मजिस्ट्रेट के पास मामले की जांच करने का पूरा अधिकार और क्षेत्राधिकार था और यदि जांच के किसी भी चरण में, मजिस्ट्रेट ने यह उचित समझा कि अन्य अतिरिक्त धाराएं भी शामिल की जानी उचित थीं। मजिस्ट्रेट को स्पष्ट रूप से उन्हें जोड़ने से रोका नहीं जाएगा जिसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान की प्रक्रिया ली जाएगी और फिर मामला उचित अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए भेजा जाएगा।

13- लेकिन अगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जाता है तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत स्टेशन और मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 190 (ए) के तहत शिकायत के माध्यम से नहीं, जाहिर तौर पर दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में मजिस्ट्रेट जांच नहीं की जा सकती क्योंकि यह पुलिस की जांच एजेंसी है। अकेले ही कानूनी तौर पर जांच करने और उसके बाद आरोप पत्र जमा करने का अधिकार है, जब तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज न की गई हो, जहां शिकायत मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया पुलिस मामले में लागू होगी, हालांकि आरोप पत्र जमा करने के बाद मामला मजिस्ट्रेट के पास जाता है। इस बारे में राय बनाने

के लिए कि क्या यह उस मामले में संज्ञान लेने और मुकदमे के लिए उपयुक्त मामला है जो एफआईआर के माध्यम से पुलिस के समक्ष दर्ज किया गया है और जांच पूरी होने के बाद मजिस्ट्रेट आरोप पत्र में किसी भी अनुभाग को बाहर नहीं कर सकते हैं या आरोप पत्र में शामिल नहीं कर सकते हैं जब पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया है,

14- इसलिए,यह प्रश्न उभरता है कि क्या शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता/अभियोजन पक्ष को उपाय मांगने से रोका जाएगा यदि जांच अधिकारी आईपीसी की सभी धाराओं को शामिल न करके अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं, जिस पर अपराध माना जा सकता है एफआईआर में प्रकट किए गए तथ्यों के बावजूद बनाया गया उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए क्योंकि यदि जांच अधिकारी किसी भी कारण से सभी अपराधों को शामिल करने में विफल रहे हैं तो अपराध का गठन करने वाली धाराओं के बहिष्कार की अनदेखी करके अभियोजन पक्ष को पूर्वाग्रह का सामना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, एफआईआर के आधार पर आरोपपत्र, जिस पर जांच की गई थी, लेकिन फिर एक और सवाल उठता है कि क्या इस कमी को मजिस्ट्रेट द्वारा भरने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके समक्ष मामला आरोपपत्र प्रस्तुत करने के बाद संज्ञान लेने के लिए आता है और जैसा कि पहले ही कहा गया है, मजिस्ट्रेट इसमें एक मामला जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है, संज्ञान लेने के समय धाराओं को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, ट्रायल कोर्ट द्वारा

धारा 216, 218 या सीआरपीसी की धारा 228 के तहत आरोप तय करने के समय ही इसकी अनुमति दी जाएगी। इसका अर्थ यह हो सकता है कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद अभियोजन पक्ष के लिए आरोप तय करने के चरण में उपयुक्त ट्रायल कोर्ट के समक्ष बहस करने का विकल्प खुला होगा ताकि यह स्थापित किया जा सके कि दिए गए तथ्यों पर अभियोजन के अनुसार उचित धाराएं लगाई जानी चाहिए। एक साथ फंसाए जाने के लिए, आरोपी को इस स्तर पर यह प्रस्तुत करने की भी स्वतंत्रता है कि किसी विशेष प्रावधान के तहत आरोप तय किया जाना चाहिए या नहीं और यह पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त मंच है कि क्या आरोप तय किया जा सकता है और एक विशेष धारा के तहत आरोप तय किया जा सकता है या नहीं। जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के साथ-साथ एफआईआर और आरोप पत्र में बताए गए तथ्यों के आधार पर जोड़ा या हटाया जा सकता है।

15- वैकल्पिक रूप से, यदि कोई मामला धारा 190 या 202 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है, तो मजिस्ट्रेट को पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। शिकायत की जांच करने और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या शिकायत में उल्लिखित धाराओं के आधार पर संज्ञान लिया जाना उचित है या आगे की धाराएं जोड़ी जानी थीं या हटा दी गई थीं, सीआरपीसी ने स्पष्ट रूप से दो तरीकों को शामिल किया है जो की शक्तियों को वर्णित

करते हैं। मजिस्ट्रेट एक शिकायत मामले में जांच करेगा और पुलिस स्टेशन में पंजीकृत मामले के आधार पर पुलिस जांच करेगा जहां पुलिस के जांच अधिकारी अध्याय XII के तहत जांच करते हैं और इन प्रक्रियाओं के संबंध में बिल्कुल कोई अस्पष्टता नहीं है।

16- अध्याय Xii के तहत पुलिस रिपोर्ट और अध्याय XIV और XV के तहत मजिस्ट्रियल शिकायत के आधार पर एक मामले में अपनाई जाने वाली इस स्पष्ट कार्रवाई के बावजूद, जब किसी दिए गए मामले में सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करने की बात आती है, तो प्रभावित पक्ष सामने आते हैं। अक्सर असमंजस की स्थिति में फंस जाते हैं, जैसा कि तत्काल मामले में हुआ है क्योंकि मजिस्ट्रेट की शक्तियां, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत के आधार पर मामले से निपटती हैं और पुलिस रिपोर्ट/एफआईआर पर आधारित पुलिस की शक्तियों को ओवरलैप करने की अनुमति दी गई है और दोनों को ओवरलैप करने की अनुमति दी गई है। कार्रवाई के अलग-अलग तरीकों को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए, जो सही प्रक्रिया नहीं है क्योंकि यह सीआरपीसी के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। प्रभावित पक्षों को खुद को अवगत कराना होगा कि अगर एफआईआर के आधार पर पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 154 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जाहिर तौर पर सही चरण यह है कि एफआईआर के आधार पर कौन सी धाराएं लागू होंगी और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री आरोप पत्र में परिणत

होगी, यह उचित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप तय करने के समय ही निर्धारित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, यदि मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज की गई शिकायत से उत्पन्न होता है, तो सीआरपीसी की धारा 190 और 200 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से पालन करना होगा।

17- चूंकि उक्त मामला पुलिस के समक्ष दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, इसलिए जोड़ या घटाव के लिए सही चरण है : धाराओं का निर्धारण आरोप तय करते समय करना होगा, लेकिन उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय और आदेश में सटीकता और स्पष्टता के साथ कारण नहीं बताए हैं और यह दर्ज करके एक आकस्मिक टिप्पणी की है कि ट्रायल कोर्ट उचित स्तर पर यह निर्धारित करने की शक्ति होगी कि मामले को अंतिम रूप से सुनवाई के लिए भेजे जाने से पहले कौन से प्रावधान लागू किए जाने हैं। उच्च न्यायालय के आदेश का नतीजा यह है कि अपीलकर्ता-गुजरात राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष को मजिस्ट्रेट के आदेश को दरकिनार करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है जहां अभियोजन पक्ष के पास याचिका में सुधार या सराहना के लिए कोई उपाय नहीं बचेगा कि क्या अतिरिक्त आरोपों को शामिल करने या बाहर करने की अनुमति दी जा सकती है। वास्तव में, विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर किया है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनके समक्ष मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया गया था, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकार क्षेत्र के गलत प्रयोग के आधार पर पुनरीक्षण की अनुमति दे सकते थे, जिन्होंने आरोप पत्र में तीन और धाराएं जोड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बजाय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ऐसा करने से सीधे तौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है, न कि खुद को क्षेत्राधिकार की त्रुटि के बारे में विचार करने और मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाए जाने वाले सही रास्ते को निर्धारित करने तक ही सीमित रखने के बजाय, वास्तव में, कार्रवाई का सही तरीका उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-गुजरात राज्य को सीआरपीसी की धारा 228 के तहत आरोप तय करते समय आरोप जोड़ने का सवाल उठाने की अनुमति दे दी और सही बात बताए बिना मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने का निरर्थक आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। प्रभावित पक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्रवाई के परिणामस्वरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तीन आदेश पारित किए गए, फिर भी यह उचित कार्रवाई पर प्रकाश डालकर विवाद का समाधान नहीं कर सका। अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाया जाना - गुजरात राज्य के साथ-साथ मजिस्ट्रेट ने भी आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद धाराएं जोड़ने की अनुमति दी, जिसमें यह गायब था कि मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज

शिकायत मामले से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि एक मामला था जो पुलिस रिपोर्ट/एफआईआर से उत्पन्न हुआ था।

18- उपरोक्त विश्लेषण के परिणामस्वरूप, हम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को स्वीकार नहीं करते हैं जिन्होंने आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद आरोप पत्र में तीन धाराएं जोड़ने की अनुमति दी थी, हमारा यह भी मानना है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय को मजिस्ट्रेट और शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाई जाने वाली कार्रवाई का सही तरीका निर्दिष्ट करना चाहिए था, जिसकी विफलता के कारण मामला इस मुकदमे में फंस गया जिससे मुकदमे की सुनवाई में बाधा उत्पन्न हुई। इसलिए हम उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन और स्पष्टीकरण करके इस अपील का निपटारा इस हद तक करते हैं कि अपीलकर्ता गुजरात राज्य उस समय जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और एफआईआर के आधार पर धाराएं जोड़ने से संबंधित सभी प्रश्न उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का मामला चूंकि मामला सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर एक पुलिस मामले से उत्पन्न हुआ है, न कि सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज शिकायत मामले से, इस प्रकार, उच्च न्यायालय हालांकि यह देखने में सही हो सकता है कि आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को मुकदमे के दौरान उचित चरण में धाराओं को शामिल या बाहर करके आरोपों को संशोधित

करने से नहीं रोका गया था, यह स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट करने के लिए न्याय और निष्पक्षता के हित में बाध्य था कि ट्रायल कोर्ट याचिका को स्वीकार करेगा और उस पर विचार करेगा। सीआरपीसी की धारा 211 के तहत आरोप तय करने के चरण में धाराएं जोड़ी गईं क्योंकि मामला पुलिस मामले से निकला था, न कि मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत मामले से, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अधिक न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता था, तदनुसार आदेश दिया गया।

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक नरेंद्र सिंह मालावत (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।